राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 155वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 27.12.2022 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 155वीं बैठक **श्री अजय कुमार खुराना**, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री महेंद्र कुमार पारख, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार, श्री महावीर प्रसाद मीणा, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, श्री बाइजू कुरूप, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री राजेश कुमार मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री कमलेश कुमार चौधरी, संयोजक, एसएलबीसी राजस्थान और महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री विकास अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री सुधांशु खमारी, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

श्री कमलेश कुमार चौधरी, महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 155वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया।

उन्होने सूचित किया कि सितंबर 2022 माह में सम्पन्न 154वी एसएलबीसी बैठक में सदन द्वारा दिये गए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान एसएलबीसी बैठक में निम्न बिन्दुओं को भी चर्चा हेतु शामिल किया गया है -

- Comparison of credit & deposit to GDP of the Rajasthan & Nearby states
- Comparison of Rajasthan with nearby states in various major parameters like growth of deposit, advance, total priority sector, agriculture, MSME etc.
- Status of districts having CD ratio lower than all India level.
- Status of districts in Rajasthan under CRISIL Inclusix index.
- Comparison of sector-wise advances of Rajasthan and nearby states.
- Review of investment credit under agriculture in Rajasthan.

एसएलबीसी की गत बैठक में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक ने राजस्थान राज्य में सभी हितधारकों के लिए एसएलबीसी को थिंक टैंक के रूप में विकसित करने की आवश्यकता व्यक्त की थी। इस संदर्भ में 30 नवंबर 2022 को, आरबीआई क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एसएलबीसी थिंक टैंक की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नाबार्ड, सीडबी, एसएलबीसी एवं एसबीआई से पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया एवं राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।

उक्त बैठक में हुई चर्चा के आधार पर लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय/सुझाव निम्नानुसार हैं-

- लीड बैंक योजना के तहत एलडीएम फॉरम को मजबूत करने के लिए सभी डीसीसी संयोजक बैंक यह सुनिश्चित करें कि एलडीएम के रूप में केवल dynamic & carrier oriented बैंक कर्मियों को पदस्थापित किया जाये एवं उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचा, पर्याप्त कर्मचारी और वाहन प्रदान करें। इसके साथ ही समय समय पर उनको उचित ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जाये ताकि एलडीएम को अपने कर्तव्यों के साथ साथ उनकी महत्ता के बारे में भी जागरूक करवाया जा सके।
- गत वर्षों में राज्य में PLP एवं ACP के लक्ष्यों में रहने वाली असमानता को अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) में ठीक करते हुए जिले की प्रत्येक शाखा स्तर से वार्षिक साख योजना के लक्ष्य निर्धारण में सहभागिता सुनिश्चित कि जाना प्रस्तावित है।
- अगले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य निर्धारण के समय इस बात पर भी ज़ोर दिया जाएगा कि जिलों के PLP एवं ACP के लक्ष्यों में समरूपता रखी जाये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) में ACP के लक्ष्य, PLP के सापेक्ष रखे जाएँ।
- साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंकों के वार्षिक ACP लक्ष्य, उनके प्रधान कार्यालयों से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार ही होने चाहिए।

उन्होने सूचित किया कि एलडीएम की त्रैमासिक रैंकिंग मार्च, 2023 तिमाही से प्रकाशित की जाएगी, जो कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। यह रैंकिंग लीड बैंक योजना में वांछित सुधार के आधार के रूप में भी काम करेगी एवं शीर्ष तीन अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मुख्य बैठक में अभिनंदन किया जाएगा।

साथ ही उन्होने बताया कि हाल ही में पुणे में हुयी एसएलबीसी संयोजकों की बैठक में 1 District- 1 Product के अंतर्गत किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने एवं विपणन में उनका सहयोग कर किसानों की आय दोगुनी करने में योगदान करने हेतु सभी राज्यों में बैंकों से आवश्यक सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के सभी सदस्यों से समस्त वित्तीय मापदण्डों पर एवं योजनाओं के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन करते हुये राज्य के समग्र विकास में अपना योगदान देने का अनुरोध किया।

उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

उन्होने निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला-

- वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत में बैंकिंग उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे स्थिर प्रणाली में से एक रहा है। जबकि दुनिया भर के देश नकारात्मक विकास और मुद्रास्फीति देख रहे हैं, अधिकांश

केंद्रीय बैंकों ने दरों में बढ़ोतरी की है और संकट से निपटने के लिए कठोर नीतिगत निर्णय लिए हैं, भारत में एक कैलिब्रेटिड और आत्मविश्वासपूर्ण वृद्धि हुई है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक, बैंकिंग उद्योग ने 17.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की ऋण वृद्धि और 9.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की जमा वृद्धि दर्ज की। साथ ही, पिछले साल की सितंबर तिमाही में भारतीय बैंकों का शुद्ध लाभ 37,567 करोड़ रुपये था, जो इस साल की समान अवधि के लिए 59 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ 60,000 करोड़ रुपये हो गया, जो भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए एक अच्छा संकेत है।
- माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैठक के दौरान बैंकरों से वैश्विक स्पिलओवर सहित उभरती व्यापक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने एवं यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उनके द्वारा सशक्त risk prevention एवं mitigation नीतियां, प्रक्रियाएं और अवसंरचना प्रभावी ढंग से लागू हैं।
- निर्यात एवं वैश्विक व्यापार की वृद्धि व भारतीय मुद्रा INR में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की रुचि बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने invoicing, भुगतान एवं आयात, निर्यात का settlement INR में करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

Latest developments in Rajasthan-

- ब्रिक और मोर्टार शाखाएं: जुलाई, 2022 के महीने में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए पूरे भारत में 363 केन्द्रों का चयन किया था जिनमें से 95 केंद्र राजस्थान के हैं। DFS, MoF, GoI के आदेशानुसार सभी बैंकों से 31.12.2022 तक आवंटित केन्द्रों पर शाखा खोलने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- हाल ही में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने General Financial Rules, 2017 में संशोधन करके, e-BG को खरीदी प्रक्रिया हेतु bid security एवं performance security के रूप में सम्मिलित किया है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने NeSL के डिजिटल e-BG platform के उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी है। सभी बैंकों से e-BG की प्रक्रिया को लागू करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- केंद्रीय बजट के अनुसार, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत कवर को बढ़ाकर 5,00,000/- करोड़ रुपये कर दिया गया है और यह योजना अब मार्च 2023 तक उपलब्ध है। राजस्थान में कुल 5.58 लाख ऋण खातों में रु. 17,825 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर दिया गया है, जिसमें से 30.11.2022 तक 14,696 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। उन्होने सभी बैंकों से एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- गुजरात (रु 4 ट्रिलियन) के बाद वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्थान ने भारतीय और विदेशी कंपनियों से 2.37 ट्रिलियन रुपये का दूसरा सबसे अधिक ताजा निवेश आकर्षित किया।

उन्होने सदस्य बैंकों को सितंबर 2022 को समाप्त छमाही में विभिन्न क्षेत्रों में निम्नानुसार सराहनीय प्रदर्शन करने पर बधाई दी-

- वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष 52% की उपलब्धि
- अटल पेंशन योजना के तहत 82% लक्ष्य उपलब्धि
- एनआरएलएम के तहत 61% लक्ष्य उपलब्धि
- पीएमईजीपी के तहत मार्जिन राशि के अंतर्गत स्वीकृति के लक्ष्य के सापेक्ष 92% उपलब्धि

साथ ही उन्होने सदस्य बैंकों से केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि प्राप्त करने एवं देश एवं राज्य के समग्र विकास हेतु योगदान करने का अनुरोध किया:

- वार्षिक साख योजना
- जन सुरक्षा योजनाएँ यथा PMSBY, PMJJBY एवं APY
- पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, StandUp India, PMFME, कृषि अवसंरचना कोश (AIF)
- इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
- इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने सदन को बताया कि:

- सितंबर 2022 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का कुल कारोबार **10.62 लाख करोड़ रुपये** के स्तर पर पहुंच गया है। बैंकों ने deposits में **12.07%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और बकाया अग्रिमों में **16.58%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि अर्जित की है।
- राज्य का सीडी अनुपात सितंबर, 2022 तक **85.23%** है जो कि आरबीआई बेंचमार्क से काफी ऊपर है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अग्रिमों में **11.56%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है जो संतोषजनक है और सितंबर, 2021 की तुलना में कृषि क्षेत्र के अग्रिमों में **12.94%** की वृद्धि हुई है।
- सितंबर 2022 तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक साख योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 52.67% की उपलब्धि है।

उन्होने सदन को बताया कि निम्न प्रकरणों पर बैंकर्स को राज्य सरकार से समर्थन की आवश्यकता है:

- विभिन्न सरकारी सब्सिडी वाली ऋण योजनाओं के तहत बैंकों की बकाया राशि को शामिल करने के लिए पीडीआर अधिनियम, 1952 में संशोधन लंबे समय से लंबित है। उन्होने राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से पीडीआर अधिनियम, 1952 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया, ताकि बैंक ऋण वसूली में तेजी लाई जा सके और सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में बढ़ते एनपीए के तनाव को कम किया जा सके।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- उन्होने भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि कृषि ऋण रहन पोर्टल पर राज्य के सभी जिलों की ऑनबोर्डिंग को पूरा करें और इसके तकनीकी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करें।

(कार्यवाही: भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

- उन्होने आर-सेटी से संबंधित 7-8 सालों से लंबित भूमि आवंटन के मामलें में राज्य सरकार के संबन्धित विभाग को वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवाने का अनुरोध किया।
- आर-सेटी द्वारा एसआरएलएम, राजस्थान सरकार को प्रशिक्षण संबंधी खर्चों के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बकाया दावे का भुगतान न होने का मामला लंबे समय से लंबित है।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

- राजस्थान RACO-RODA अधिनियम, 1974 के तहत राशि लगभग रु. 3,300 करोड़ के लगभग 1.44 लाख रोडा मामले जिला/ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं। रु. 2,000 करोड़ के 0.93 लाख से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।
- संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा सरफेसी अधिनियम के मामलों में अनुमति प्रदान करने में असामान्य देरी के मुद्दे में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस संबंध में, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निपटान करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी भी लगभग रु. 337 करोड़ के 2,029 मामले ज़िला प्राधिकारियों के पास लंबित हैं, जिनमें से रु. 229 करोड़ के 1384 मामले लगभग 60 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।
- राको-रोडा और सरफेसी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में वसूली को गति देने के लिए राज्य में एक उपयुक्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

- **(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)**

उन्होने सदन को सूचित किया कि माननीया वित्त मंत्री, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, लोक सभा 08.01.2023 में कोटा जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँगे। उन्होने सभी हितग्राहकों से इन क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में पूर्ण निष्ठा के साथ सहभागिता करने का अनुरोध किया।

उन्होने राज्य में विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में समन्वय हेतु केंद्र / राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थिति गणमान्य सदस्यों व सभी पधारे हुए अतिथियों का अभिनंदन किया व बताया कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक कारकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अवसर और चुनौतियां दोनों ही प्रदान की हैं-

चुनौतियां- भारतीय अर्थव्यवस्था का रुझान वृद्धियात्मक है, पर वित्तीय संस्थानों को इस रुझान की अंतर्धारा एवं KPIs पर ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक आर्थिक कारकों, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं आवश्यक तैयारियों के संबंध में बैंकों एवं वित्तीय क्षेत्र की अन्य इकाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है।

अवसर- विकास, निवेश, ऋण वितरण, GDP इत्यादि के संदर्भ में भारत आज वैश्विक स्तर पर एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। लेकिन इसके साथ ही हमें प्रक्रियाओं एवं पद्यतियों को भी

सशक्त करने की आवश्यकता है। देश के कई राज्य, मेट्रो शहर वित्तीय मापदण्डों पर राजस्थान से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तकनीकी एवं डिजिटलिकरण को लेन-देन की संख्या, ग्राहक संतुष्टि एवं बैंकिंग प्रणाली को धोखा धड़ी से सुरक्शित रखने के उद्देश्य से यथाशीघ्र अपनाने से बैंकों के प्रदर्शन को गति मिलेगी।

बाज़ार एवं अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं उपभोगताओं का अर्थव्यवस्था में बढ़े हुये विश्वास का लाभ उठाने का ये अच्छा अवसर है।

बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र को अधिक intelligently inclusive एवं digitally inclusive बनने की आवश्यकता है। सभी वित्तीय इकाइयों को पहले राष्ट्र, फिर राज्य और अंत में balance-sheet के बारे में विचार करना चाहिए। 'अधिक संख्या' एवं 'बेहतर चयन' के सिद्धांतों का उपयोग करते हुये समावेशन के साथ वित्तीय लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

सरकारी योजनाओं के संदर्भ में उन्होने बताया कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य कोर बैंकिंग एवं कोर बीमा को सहयोग एवं बढ़ावा देना है जिससे वित्तीय संस्थान अपने निर्धारित लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त कर सकें। इनके माध्यम से बैंकों द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों हेतु बड़ी संख्या में स्वतः ही लोगों को आकर्षित किया जा सकता है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य सदस्यों व समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन किया।

उन्होने बताया कि समिति की पिछली बैठक में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने सभी हितधारकों से इस forum को राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर एक बौद्धिक थिंक टैंक बनाने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी करने का अनुरोध किया था ताकि हम राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति में राज्य सरकार के प्रयासों में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी संयोजक बैंक, डीसीसी संयोजक बैंकों, नाबार्ड, सिडबी, कुछ एलडीएम और डीडीएम के साथ वर्तमान परिदृश्य को समझने एवं आगे का रोडमैप बनाने हेतु बैठक की।

बैठक में हुई चर्चा के दौरान निम्न सुझाव सामने आए-

- नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया PLP एवं एसएलबीसी द्वारा तैयार की गयी वार्षिक साख योजना के मध्य असमानता को कम करना आवश्यक है। वार्षिक साख योजना की तैयारी में bottom up approach की पालना की जानी चाहिए, अर्थात वार्षिक साख योजना की तैयारी का आरंभ PLP के अनुरूप शाखा स्तर से किया जाना चाहिए। इस हेतु सभी की सहमति से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 2-3 जिलों में निष्पादित किया जाना निश्चित किया गया है।
  उन्होने सभी बैंक जिनके पास अग्रणी बैंक का कार्यभार है से PLP की तैयारी में bottom up approach की पालना करवाने में एसएलबीसी का सहयोग करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: डीसीसी संयोजक बैंकस)

- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक अग्रणी बैंक योजना के मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। अग्रणी बैंक योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रणी बैंक का कार्यभार संभालने वाले बैंकों से अनुरोध है कि वह गतिशील एवं प्रगति उन्मुख स्टाफ को ही अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों के रूप में चयनित करें एवं उपयुक्त और पर्याप्त श्रमशक्ति (manpower) एवं अवसंरचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंकस)

- बैंकों द्वारा DCC/ DLRC बैठकों हेतु ज़िला समन्वयक चयनित किया जाता है जो कि अधिकतर उस क्षेत्र की किसी मुख्य शाखा के शाखा प्रबन्धक होते हैं। ऐसे में इन ज़िला समन्वयकों को जिले के मामलों का न तो ज्यादा ज्ञान होता है और न ही रुचि, साथ ही ज़िले के बाकी शाखा प्रबन्धकों का सहयोग प्राप्त नहीं होता। सभी बैंकों से अनुरोध है कि जिन जिलों में पर्याप्त शाखाएँ कार्यरत हैं उन जिलों में वह ज़िला समन्वयक की जिम्मेदारी अंचल अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ को ही दि जानी चाहिए। जिससे ज़िला समन्वयक अपने उद्देश्य को ठीक प्रकार से पूरा कर सकें।
- बैंक मित्रों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ असक्रिय बैंक मित्रों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। बैंक मित्र वित्तीय साक्षारता, वित्तीय समावेशन, वित्तीय जागरूकता व केंद्र एवं राज्य सरकार तथा बैंकों की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बैंकों से अनुरोध है कि असक्रिय बैंक मित्रों की संख्या में वृद्धि के कारणों की जांच करें एवं इनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करें। साथ ही अधिक से अधिक महिला बैंक मित्रों को नियुक्त कर महिला सशक्तिकरण एवं 1BC-1GP के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान प्रदान करें।
- बैंकों को MSME financing बढ़ाने हेतु और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। टेक्नोलोजी एवं end-to-end डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से सूक्ष्म उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों की प्रोसेसिंग कॉस्ट को कम किया जा सकता है। ऐसी कई तकनीकें हैं जो behavioural parameters के आधार पर क्रेडिट मूल्यांकन करते हैं।
- विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बैंकों द्वारा फिनटेक को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास में और अधिक निवेश आ सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य की कुछ आर-सेटियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि-

- आरसेटी द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण के अंतर्गत और अधिक गतिविधियों को सम्मिलित करते हुये प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है।
- जिन प्रशिक्षुओं ने आर-सेटी के 30-45 दिनों के आवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिए है उन प्रशिक्षुओं का भी अपर्याप्त राशि का क्रेडिट लिंकेज किया गया है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वह अपने अंतर्गत आर-सेटी के प्रशिक्षुओं का उपयुक्त राशि का क्रेडिट लिंकेज करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त आर-सेटि संयोजक बैंक)

उन्होने बताया की विपरित (crisis) परिदृश्य में ग्राहक संतुष्टी की महत्ता का पता चलता है। यदि हम हमारे ग्राहकों को संतुष्ट रखेंगे तो विपरित (crisis) की स्थिति में भी उसका विश्वास हमारे साथ बना रहेगा इससे बैंक की साख/ गरिमा को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह अपने internal grievance mechanism को सशक्त करना सुनिश्चित करें

जिससे ग्राहकों की शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के पास आने से पहले ही बैंक स्तर पर निस्तारण हो जाएँ।

उन्होने यथासमय तिमाही अंत के 45 दिनों में एसएलबीसी मुख्य बैठक आयोजित करवाने हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को आवश्यक डाटा समय से प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को निम्नलिखित उपलब्धियों के लिए बधाई दी-

- वार्षिक साख योजना के अंतर्गत 50% से अधिक लक्ष्य की उपलब्धि
- भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी, नाबार्ड आदि के साथ मिलकर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के एजेंडा पर विचार विमर्श कर एजेंडा में सुधार/ संशोधन करना एवं संशोधित एजेंडा का इस बैठक से लागू करना।

उन्होने बताया कि-

- राष्ट्रीय एजेंसियों ने पूर्वानुमान दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी एवं विकास दर मजबूत होगी। इससे क्रेडिट, बीमा और वित्तीय समावेशन आदि के क्षेत्र में बैंकों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे।
- दिनांक 30.09.2022 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम रु 1.21 लाख करोड़ के स्तर पर था जो की वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य का 53% है। साथ ही कृषि अग्रिम, एमएसएमई ऋण एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वार्षिक साख योजना के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.09.2022 तक क्रमशः 48%, 74% एवं 17% रहे। अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अतिरिक्त वार्षिक साख योजना में प्रदर्शन संतोषजनक है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- दिनांक 30.09.2022 को कृषि क्षेत्र में ऋण निर्धारित लक्ष्य का 48% (रु 62,810 करोड़) है जो की 30.09.2021 में वार्षिक साख योजना का लक्ष्य का 53% (रु 64,892 करोड़) था। साथ ही कृषि सावधि ऋण में भी बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक है जो की चिंता का विषय है।
- राजस्थान के कृषि क्षेत्र का सकाल घरेलू उत्पाद में योगदान 30% है। कृषि क्षेत्र में flow of funds बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सावधि ऋण प्रदान करने की आवश्यकता है। राजस्थान में माध्यम एवं बड़े साइज़ की कृषि भूमि बाकी राज्यों की तुलना में अधिक है। राज्य सरसों, बाजरा इत्यादि का सबसे बड़ा उत्पादक, मूँगफली, दूध इत्यादि का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके पश्चात भी कृषि क्षेत्र को पर्याप्त क्रेडिट फ्लो नहीं हो रहा है।
- 08.12.2022 को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की क्रेडिट क्षमता पर विचार विमर्श किया गया था, जिस दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की क्रेडिट क्षमता रु 2.75 लाख करोड़ आंकी गई है, जिसमें से 1.63 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र की अनुमानित

क्षमता है। इस क्षमता का वित्त वर्ष 2023-24 के एसीपी लक्ष्यों के साथ सामंजस्य करने की आवश्यकता है।

- मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को केसीसी प्रदान करने हेतु 15.09.2022 से राष्ट्रव्यापी केसीसी संतृप्ति अभियान फिर से शुरू किया है। उन्होने सभी बैंकों से केसीसी संतृप्ति अभियान के अंतर्गत allied गतिविधियों हेतु अधिक से अधिक केसीसी प्रदान करने एवं प्रगति को जन सुरक्षा पोर्टल पर समयोचित अद्यतित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के अंतर्गत राज्य में बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक है। AIF के अंतर्गत सावधि कृषि अग्रिम हेतु क्रेडिट गारंटी कवर के अतिरिक्त ब्याज सब्वेंशन भी दिया जाता है।
- नाबार्ड द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से सहकारी समितियों को पुनर्जीविक करने का प्रयास किया जा रहा है। AIF के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं सहकारी समितियों को 3% की रियायती दर पर विस्तारित की जा रही हैं।
- वित्तीय समावेशन कोष (FIF) के तहत इस वर्ष राजस्थान को रु 42 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उन्होने सभी बैंकों से FIF की राशि का वित्तीय समावेशन हेतु उपयोग करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य के कुछ जिलों में सीडी अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 60% के कम है, जिसके कारण समाज का कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाएं औपचारिक ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गयी है।
- देश भर में एसएचजी का प्रति व्यक्ति ऋण उन जिलों में कम है जहां सीडी अनुपात कम है।
- नाबार्ड राज्य की वित्तीय संस्थानों को अधिकतम संसाधन उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। सभी हितग्राहकों को राज्य में वित्तीय समावेशन में प्रगति करने हेतु और अधिक प्रयत्न करना चाहिए।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि व्यापार, उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने में बैंकर्स की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में समाज के कमजोर वर्ग के लिए रोजगार सृजन हेतु दो योजनाएं हैं- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना।

<u>मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना</u>- योजनान्तर्गत बैंकों को अग्रेषित किए गए आवेदनों की संख्या (14374) संतोषजनक है, साथ स्वीकृत किए गए आवेदनों एवं जिन आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है, की संख्या में अंतर कम हुआ है (774)।

भारतीय स्टेट बैंक का योजनान्तर्गत प्रदर्शन असंतोषजनक एवं चिंतनीय है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट् एवं ईक्विटास स्माल फ़ाइनेंस बैंक द्वारा

आवेदनों को प्रोसैस करने की गति बहुत कम है। उन्होने आईसीआईसीआई बैंक के प्रदर्शन की सराहना की एवं भारतीय स्टेट बैंक एवं कम प्रदर्शन वाले बैंकों से योजना में बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होने सभी बैंकों से लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना-</u> पीएमईजीपी के तहत अधिकतम परियोजना लागत को विनिर्माण क्षेत्र के लिए बढ़ाकर रु 50 लाख कर दिया गया है। योजनान्तर्गत अस्वीकृत एवं लंबित आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वह आवेदन को अस्वीकार करने से पहले अस्वीकार करने के कारणों की गंभीरता से जांच करें एवं लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

इसके पश्चात उन्होने **डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना,** जिसे बजट 2022-23 में लॉन्च किया गया था, का विवरण सदन के सामने रखा एवं सभी बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी अपने स्तर से अपने निचले कार्यालयों को योजना परिपत्र के अनुसार योजना के बारे में जानकारी का प्रसार करें एवं बैंकों को योजनान्तर्गत बैंकों को अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने आशा जताई की सभी बैंक केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुये राज्य में व्यवसाय एवं उद्योगों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** को बैठक एजेंडा बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ हेतु आमंत्रित किया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

<u>Confirmation of Minutes of 154th SLBC Meeting (28.09.2022)</u>

सर्वप्रथम उन्होने बताया कि दिनांक 28.09.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 07.10.2022 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

<u>Issues pending with the State Governement</u>

कार्यवाही बिन्दु- PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करना।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को सूचित किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा PDR Act के संशोधन के संबंध में प्रेषित किए गया प्रस्ताव उनके कार्यालय द्वारा वित्तीय विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है। जल्दी ही राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

कार्यवाही बिन्दु- कृषि ऋण रहन पोर्टल को सभी जिलो में लागू करना व जयपुर व झुंझुनु जिले में कृषि ऋण रहन पोर्टल में आ रही समस्याओं के संबंध में दूर करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही किया जाना।

(कार्यवाही: भू-प्रबंधन विभाग एवं राजस्व विभाग)

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि कृषि ऋण रहन पोर्टल में आ रही समस्याओं की राज्य सरकार द्वारा जांच कारवाई जा रही है एवं इन्हे सुधार किया जा रहा है।

उन्होने राको-रोडा के संबंध में सूचित किया कि SDM द्वारा राको-रोडा के अंतर्गत मामलों को स्वीकार नहीं करने के संबंध में उनके विभाग द्वारा संबंधितों को पत्र लिख दिये गए थे एवं उनके विभाग को इस संबंध में किसी भी बैंक से कोई नया पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि किसी प्रकरण में SDM द्वारा राको-रोडा के अंतर्गत मामलों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो ऐसे प्रकरणों की सूचना वह राजस्व विभाग को देना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

कार्यवाही बिन्दु- पाली, जालोर व अलवर जिलों में आर-सेटी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन से संबन्धित सभी मुद्दे एवं डूंगरपुर व सिरोही जिलों में आर-सेटी भवनों के निर्माण के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा AG ऑडिट में विभिन्न प्रभारों की वसूली से संबन्धित मुद्दे।

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि इन प्रकरणों में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अनुरोध किया कि संबन्धित अधिकारियों को राजस्व विभाग में भेजें जिससे इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा सके।

परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि जालोर के कलक्टर ने राजस्व विभाग को जालोर में भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

साथ ही 07.12.2022 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान AG ऑडिट में विभिन्न प्रभारों को माफ करने के तरीकों पर चर्चा की गयी।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि 07.12.2022 की बैठक में मुख्य सचिव महोदया ने सभी कलक्टरों को RSETI संबन्धित मुद्दों की बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है एवं इस हेतु उन्होने राज्य सरकार को धन्यवाद किया।

कार्यवाही बिन्दु- इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (IGSCCY) में कम प्रगति वाले बैंकों को सरकारी व्यवसाय प्रदान न करें एवं दिया गया सरकारी व्यवसाय वापस ले लें।

प्रतिनिधि, वित्त एवं कर विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि मुख्य सचिव महोदया के स्तर से सभी बैंकों के सरकारी योजनान्तर्गत प्रदर्शन की समीक्षा की गयी है एवं प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा पुनः इस हेतु बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया की सरकारी योजनान्तर्गत अपने प्रदर्शन को गंभीरता से लें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

कार्यवाही बिन्दु - बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड (बैंक शाखा की जानकारी) प्रदर्शित करने पर लगाने वाले शुल्क में छूट प्रदान किया जाना।

बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट से संबन्धित प्रकरण के निस्तारण के संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा विभिन्न राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश में लागू दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु इन राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों को दिनांक 30.09.2022 को पत्र लिखा गया। इस संबंध में एसएलबीसी गुजरात द्वारा सूचित किया गया है कि उनके राज्य में बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड प्रदर्शित करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से ग्लो साइन बोर्ड प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क के संबंध में एसएलबीसी गुजरात द्वारा प्रेषित किए गए दस्तावेज़ उनके विभाग को अग्रेषित करने का अनुरोध किया।

कार्यवाही बिन्दु- आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Committee) की 9 सिफ़ारिशों पर कार्यवाही।

प्रतिनिधि, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि उनके द्वारा सभी 9 सिफ़ारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक को अद्यतन प्रेषित कर दिया गया है।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग से आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Committee) की सिफ़ारिशों पर point by point उत्तर देने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

कार्यवाही बिन्दु- Status of pending Claims submitted by RSETIs through SDR to SRLM, GoR as on 30.09.2022

परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सूचित क्या कि उनके कार्यालय ने रु 37 करोड़ का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को प्रेषित कर दिया है। उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से भी उक्त मुद्दे पर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुवर्तन की कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

<u>Banking at a glance in Rajasthan</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति संतोष जनक है-

Parameters	Sept, 2019	Sept, 2020	Sept, 2021	March, 2022	Sept, 2022*
No. of Branches (New Br in Yr.)	8,015 (105)	8,189 (52)	8,194 (31)	8,315 (187)	8,347 (42)
***Around 68.59% branches in Rural & Semi Urban.**					
Amt. in Rs. Crore					
Deposits (% Y-o-Y Growth)	4,17,917 (11.31%)	4,68,622 (7.97%)	5,11,415 (9.13%)	5,47,105 (10.43%)	5,73,164 (12.07%)
Advances (% Y-o-Y Growth)	3,38,224 (15.08%)	3,74,504 (3.97%)	4,19,042 (11.90%)	4,66,511 (14.08%)	4,88,501 (16.58%)
CD Ratio	83.87%	81.87%	83.51%	87.14%	85.23%
PS Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	2,19,735 (12.02%) (64.97%)	2,41,799 (10.04%) (64.57%)	2,70,851 (12.01%) (64.64%)	3,00,798 (16.98%) (64.48%)	3,02,148 (11.56%) (61.85%)
Agri. Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	1,03,059 (3.64%) (30.47%)	1,13,502 (10.13%) (30.31%)	1,24,760 (9.92%) (29.77%)	1,37,100 (12.83%) (29.39%)	1,40,900 (12.94%) (28.84%)
MSME Advances (% Y-o-Y Growth) (% of total advances)	79,263 (14.01%) (23.44%)	89,329 (12.70%) (23.85%)	1,05,646 (18.27%) (25.21%)	1,20,943 (27.37%) (25.93%)	1,23,706 (17.09%) (25.32%)

Achievement against stipulated benchmark on September 2022

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में 1.91% की गिरावट आई है।
- कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी में 2.63% की गिरावट आई। हालांकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में रु. 1,350.19 करोड़ की बढ़ौतरी हुयी ।
- एमएसएमई के तहत उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) की आवश्यकता के कारण माइक्रो खातों में 1.88% की कमी आई है। उन्होने सभी बैंकों से, मुख्य रूप से एसबीआई, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अनुरोध किया कि माइक्रो उद्यमों का यूआरसी लेकर उनका वर्गीकरण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: एसबीआई, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक व समस्त सदस्य बैंक)
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में रु. 10,822 करोड़ की गिरावट आई है। (नेट गिरावट रु. 8,430 करोड़ रुपये)

Growth in GSDP from 2021-22 to 2022-23

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि 2021-22 (estimated) से 2022-23 (projected) तक राज्य-वार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निम्नानुसार है-

गुजरात-13.32% उत्तर प्रदेश- 17.10%
राजस्थान-11.54% तेलंगाना- 13.00%
मध्य प्रदेश- 11.10% हरयाणा-10.94%
पंजाब-9.76%

Y-o-Y Growth under various parameters in near by States (as on Sept 2022)

	Deposit	Advances	TPS	Agriculture	MSME
Rajasthan	12.07	16.58	11.56	12.94	17.09
U.P.	8.94	11.30	-23.82	7.34	-44.05
Gujarat	18.21	11.09	19.68	14.33	32.28
Haryana	7.05	16.19	15.16	-2.42	36.40

Comparison of Credit to GDP & Deposit to GDP %age of the States

- राजस्थान में क्रेडिट से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात गुजरात, मध्य प्रदेश से अधिक है लेकिन उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और पंजाब से कम है। क्रेडिट से सकाल घरेलू उत्पाद का अनुपात बढ़ाने हेतु बैंकों को कुछ जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राजस्थान के सभी जिलों में क्रेडिट penetration पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राजस्थान में डिपॉज़िट से जीडीपी का अनुपात गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से कम है। डिपॉज़िट से जीडीपी का अनुपात को बढ़ाने के लिए बैंकों को राजस्थान के उन जिलों में वित्तीय साक्षरता फैलाने की आवश्यकता है जहां जनता बैंकों में अपनी जमा राशि रखने में रूचि नहीं रखती है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- उक्त सभी मापदण्डों में राजस्थान जिन राज्यों से पिछड़ रहा है, उनसे आगे बढ्ने ने लिए कार्यवाही बिन्दु (action points) पर थिंक टैंक की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को इन राज्यों में उद्योगों एवं निवेश का समर्थन करने वाली सरकार की नीतियों का अध्ययन करना चाहिए जिससे राजस्थान में भी उद्योगों की संख्या एवं निवेश राशि को बढ़ावा दिया जा सके।

(कार्यवाही: थिंक टैंक के सभी सदस्य एवं राजस्थान सरकार)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड की टिप्पणी- गैर- बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दिये गए क्रेडिट में राजस्थान की अन्य राज्यों के सापेक्ष स्थिति का डाटा भी लिया जाये।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि गैर- बैंकिंग संस्थान एसएलबीसी के सदस्य नहीं हैं एवं इनके संबंध में डाटा भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही उपलब्ध होता है।

Movement of CD Ratio in Districts

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जिलेवार सीडी अनुपात सदन के सामने रखा।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- जिन जिलों का सीडी अनुपात संतोषजनक नहीं है उनकी एक बैठक आयोजित किया जाए जिसमे उनके सीडी अनुपात के प्रदर्शन पर एवं अनुपात बढ़ाने की दिशा में चर्चा की जा सके।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने उदयपुर के सीडी अनुपात की सितंबर 2022 में जून 2022 के सापेक्ष नकारात्मक वृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से उदयपुर एवं सिरोही ज़िले के सीडी अनुपात की ब्लॉक-वार समीक्षा करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

Districts with CD ratio

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
8	>100%	Barmer, Bhilwara, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhalawar, Pratapgarh, Sri Ganganagar and Tonk
15	71-100%	Alwar, Banswara, Baran, Bharatpur, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Dausa, Jaipur, Jalore, Jodhpur, Nagaur, Sawai Madhopur and Sikar
8	61-70%	Ajmer, Dholpur, Jhunjhunu, Karauli, Kota, Pali, Rajsamand and Sirohi
2	51-60%	Dungarpur and Udaipur

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- डुंगरपुर एवं उदयपुर को 60% के बेंचमार्क के ऊपर लाने एवं इसके पश्चात राष्ट्रीय बेंचमार्क 74.80% से ऊपर लाने का लक्ष्य है।

Districts having CD ratio lower than all India level (as on September 22)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किए कि राज्य के 13 जिलों यथा बांसवाड़ा, दौसा, भरतपुर, पालि, झुञ्झुणु, कोटा, सिरोही, करौली, अजमेर, राजसमंद, धोलपुर, उदयपुर एवं डुंगरपुर का सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत (74.80%) से कम है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त जिलों का डिविज़न-वार औसत निकालने एवं इस मुद्दे पर थिंक टैंक में चर्चा करने का अनुरोध किया।

SWOT Analysis to improve the Banking facilities & financial inclusion in Banswara, Barmer, Karauli, Dholpur, Sirohi and Pratapgarh Districts

- 154वीं तिमाही की एसएलबीसी बैठक के दौरान, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने बताया कि राजस्थान में सी:डी अनुपात (87.14%) अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।
- हालाँकि, कुछ जिले जैसे बांसवाड़ा, बाड़मेर, करौली, धौलपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ CRISIL और RBI वित्तीय समावेशन सूचकांक में सबसे नीचे हैं।
- धौलपुर प्रति शाखा व्यक्तियों के मामले में देश के निचले 10% जिलों में से है और बाड़मेर प्रति व्यक्ति बचत के मामले में देश के निचले 10% जिलों में से एक है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने उपरोक्त 6 जिलों के नाबार्ड के अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ)/अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम)/जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) को SWOT विश्लेषण करने और जिलों

के सभी ब्लॉकों में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार और वित्तीय समावेशन के लिए नियमित आधार पर (मासिक) आर-सेटी, FLC, जमा, अग्रिम, वित्तीय समावेशन की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

- एसएलबीसी राजस्थान ने बांसवाड़ा, बाड़मेर, करौली, धौलपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ जिले के अग्रणी जिला प्रबंधकों और संबंधित जिलों के डीडीएम, नाबार्ड से लीड जिला अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने का अनुरोध किया है।
- आगामी तिमाही में सभी प्रमुख हितधारकों यथा आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, डीसीसी संयोजक बैंकों की उपस्थिति में सभी एलडीएम के लिए कॉन्क्लेव का प्रस्ताव कर रहे हैं और एलडीएम का sensitization और ग्रूमिंग इस कॉन्क्लेव का प्रमुख एजेंडा होगा।
- 12.12.2022 को आयोजित 19वीं संचालन समिति की बैठक में, संयोजक, एसएलबीसी ने एलडीएम के लिए रेटिंग तंत्र का प्रस्तावित किया है।
- इस रेटिंग मैट्रिक्स को शुरू करने का विचार अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को संबंधित जिले के विकास की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है।
- इस मैट्रिक्स में 9 मापदंडों की पहचान की गई है और कुल 100 अंक आवंटित किए गए हैं।
- रैंकिंग मार्च 2022 से शुरू की जाएगी और आगामी तिमाही की एसएलबीसी बैठक में घोषित की जाएगी।
- शीर्ष 3 एलडीएम को बैठक में आमंत्रित किया जाएगा ताकि कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके।

Ranking for Quarterly Achievement for Lead District Managers

S. No.	Name of Scheme/Product	Marking Criteria	Maximum Marks
1.	CD Ratio	% age growth from Last Quarter	15 marks
2.	Annual Credit Plan (ACP)	Total Priority Sector Target Achievement %	15 marks
3.	Share of Investment Credit in Total Agriculture	% age growth from Last Quarter	10 marks
4.	Growth under MSME	Growth in % (Y-o-Y)	10 marks
5.	Performance under Social Security Schemes (PMSBY, PMJJBY & APY)	Achievement of F.Y. Targets	10 marks
6.	Performance of SHG finance under NRLM	Achievement of F.Y. Targets	10 marks
7.	Status of Financial Literacy - FLCs & Camps by Rural branches.	No. of Camps against Targets	10 marks
8.	Performance under various Schemes – AIF, PMFME (ODOP Product) & Efforts towards Implementation of schemes (coordination with Govt. Department & Preparing market etc.)	Achievement of F.Y. Targets	10 marks
9.	Timely Submission of Data to all stake holders	-	10 marks
		Total Marks	100 marks

प्रतिनिधि, सिडबी का सुझाव- एमएसएमई के अंतर्गत वृद्धि की 15 अंक एवं 'Performance under various Schemes - AIF, PMFME (ODOP Product) & Efforts towards Implementation of schemes (coordination with Govt. Department & Preparing market etc.)' के अंतर्गत 15 अंक आवंटित किए जाएँ।

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक का सुझाव- अंकन मापदंड (marking criteria) एवं आवंटित अंकों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को 1 सप्ताह में अपने सुझाव प्रदान करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही बिन्दु: भारतीय रिजर्व बैंक)

<u>Comparative Development of the Districts: CRISIL Inclusix Index</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- क्रिसिल इनक्लूसिक्स एक अद्वितीय, मजबूत विश्लेषणात्मक उपकरण और एक सापेक्ष सूचकांक है जो बुनियादी वित्तीय सेवाओं के विभिन्न रूपों को शामिल करता है।
- यह 4 tangible और महत्वपूर्ण आयामों पर आधारित है, जिनमे राजस्थान की स्थितिनिम्न प्रकार हैं:
    - Branch penetration (BP)- Above Average
    - Credit penetration (CP)- Below Average
    - Deposit penetration (DP)- High
    - Insurance penetration (IP)- Below Average
- सकल भारतीय इंक्लूसिक्स स्कोर 58.0 है। क्रिसिल इन्क्लूसिक्स वॉल्यूम 4 (वित्तीय वर्ष 2016 पर आधारित) के अनुसार, राजस्थान राज्य का क्रिसिल इनक्लूसिक्स स्कोर वित्तीय वर्ष 2013 में 39.4 (औसत से कम) से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2016 में 50.9 (औसत से अधिक) तक पहुंच गया है जिसका कारण ऋण डिपॉज़िट पेनिट्रेशान में वृद्धि है। बिहार, यूपी और एमपी बड़े राज्य हैं जिनका स्कोर राजस्थान से कम है। राजस्थान का कोई भी जिला शीर्ष 50 जिलों में नहीं है और 1 जिला यानी प्रतापगढ़ पूरे भारत में नीचे के 50 जिलों में है।
- इंक्लूसिक्स इंडेक्स स्कोर में राज्य के शीर्ष 6 ज़िले जयपुर (76.6), अजमेर (73.8), चित्तोडगढ़ (63.8), श्री गंगानगर (63.4), कोटा (61.5) एवं पालि हैं एवं नीचे वाले 6 ज़िले प्रतापगढ़ (22.8), धौलपुर (27.1), करौली (31.4%), बाड़मेर (31.7), बांसवाड़ा (34.6) एवं भरतपुर (37.4) हैं।
- सितंबर 2022 तक राज्य में प्रति लाख जनसंख्या 12 शाखाएँ, 1,21,834 CASA खाते, 22,277 ऋण खाते एवं 31,169 बीमा हैं।
- 30.09.2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम शाखा पेनिट्रेशन वाले ज़िले जयपुर (19), श्रीगंगानगर (17), कोटा (15), अजमेर (14) एवं हनुमानगढ़ (14) हैं एवं न्यूनतम शाखा पेनिट्रेशन वाले ज़िले धौलपुर (6), बाड़मेर(7), प्रतापगढ़ (8), करौली (8) एवं बांसवाड़ा (8) हैं।
- 30.09.2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम डिपॉज़िट पेनिट्रेशन (प्रति लाख व्यक्ति CASA खातों की संख्या) वाले ज़िले जयपुर (2,58,072), जैसलमेर (1,42,443), भीलवाडा (1,26,859),

चित्तौड़गढ़ (1,22,882) एवं पाली (1,12,022) हैं एवं न्यूनतम डिपॉज़िट पेनिट्रेशन वाले ज़िले प्रतापगढ़ (26,529), धौलपुर (29,182), जलोर (32,611), करौली (33,066) एवं नागौर (34,558) हैं।

- 30.09.2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम क्रेडिट पेनिट्रेशन वाले ज़िले जयपुर (40,295), हनुमानगढ़ (31,894), श्रीगंगानगर (31,116), चित्तौड़गर्ग (27,684) एवं अजमेर (27,278) हैं एवं न्यूनतम क्रेडिट पेनिट्रेशन वाले ज़िले धौलपुर (7,058), करौली (10,345), सिरोही (12,144), भरतपुर (12,259) एवं बांसवाड़ा (12,992) हैं।
- 30.09.2022 तक प्रति लाख जनसंख्या अधिकतम बीमा पेनिट्रेशन वाले ज़िले जैसलमर (92,632), कोटा (50,792), टोंक (43,696), राजसमंद (43,521) एवं भीलवाड़ा (40,775) हैं एवं न्यूनतम बीमा पेनिट्रेशन वाले ज़िले भरतपुर (20,927), धौलपुर (21,076), नागौर (21,504), जयपुर (22,467) एवं जालोर (24,215) हैं।

उन्होने सूची में निचले स्थान पर रहने वाले उक्त सभी जिलों को शाखा, डिपॉज़िट, क्रेडिट एवं बीमा पेनिट्रेशन में सुधार करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, धौलपुर, प्रतापगढ़, करौली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, नागौर, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं जयपुर)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- जिलों द्वारा उक्त प्रदर्शन को वार्षिक साख योजना बनाते समय संग्यान में लें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)

Snapshot of Sector wise Advances in Near by States (as on 30.09.2022)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्यों की क्षेत्रवार अग्रिम की स्थिति निम्नानुसार सूचित की:

	Rajasthan		Uttar Pradesh		Gujarat		Tamil Nadu		Haryana		Madhya Pradesh	
	Amount O/s	%age Share	Amount O/s	%age Share	Amount O/s	%age Share	Amount O/s	%age Share	Amount O/s	%age Share	Amount O/s	%age Share
Agriculture	140900	28.85	188574	25.1	108985	14.13	489488	23.92	76137	17.03	126492	33.37
MSME	123706	25.33	78361	10.43	192637	24.97	230478	19.05	107377	24.02	72685	19.18
Other Priority Sector	37543	7.69	28057	3.73	83301	10.8	73613	6.08	29704	6.64	36345	9.59
Non Priority Sector	186283	37.14	456296	60.74	386500	50.1	616424	50.94	233855	52.31	143523	37.86

Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 30.09.2022)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि दिनांक 30.09.2022 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों की कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण प्रतिशत क्रमशः 25.57%, 1.57%, 8.60% एवं 99.97% हैं।

राष्ट्रीय औसत के कम कुल कृषि ऋण के प्रतिशत के रूप में निवेश ऋण वाले बैंक निम्नानुसार हैं- बीआरकेजीबी (0.73%), आरएससीबी (3.25%), आरएमजीबी (3.28%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (5.05%), यूको बैंक (5.18%), आईडीबीआई बैंक (7.39%), केनरा बैंक (8.07%), भारतीय स्टेट बैंक

(8.12%), पंजाब और सिंध बैंक (11.63%), पंजाब नेशनल बैंक (14.79%), इंडियन बैंक (14.89%), बैंक ऑफ बड़ौदा (17.78%), आईसीआईसीआई बैंक (20.9%) एवं यूनिओन बैंक ऑफ इंडिया (22.43%)।

राज्य में कुल निवेश ऋण कुल कृषि ऋण का 24.65% है जिसे कम से कम 40% तक ले जाने हेतु सभी बैंकों, विशेषकर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों को सतत प्रयत्न करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों के प्रदर्शन को असराहनीय बताया एवं उन्हे अपना प्रदर्शन सुधारने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरिधारा ग्रामीण बैंक एवं समस्त सहकारी बैंक)

प्रतिनिधि, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सूचित किया कि उनके बैंक द्वारा प्रेषित डाटा में त्रुटि है एवं 30.09.2022 तक कुल कृषि ऋण के सापेक्ष कृषि में निवेश ऋण 8.62% है।

प्रतिनिधि, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने सूचित किया कि उन्होने मरुधरा ऐग्रो के नाम से रु 16 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है। साथ ही कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से निवेश ऋण हेतु प्रस्ताव आना अपेक्षित है। उनका बैंक AIF योजना के अंतर्गत exposure बढ़ाते हुये निवेश ऋण बढ़ाने कि दिशा में प्रयासरत हैं।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा गलत डाटा प्रेषित करने के संबंध में नाराजगी व्यक्त की।

(कार्यवाही: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान)

<u>Annual Credit Plan 2022-23</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रु॰ 2,29,076 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सितंबर, 2022 तिमाही तक 52.67% उपलब्धि रही है जिसके असंतोषजनक होने का कारण बैंकों द्वारा माइक्रो उद्यमों का उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लेने के कारण इन खातों का गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकृत होना है। कृषि में 47.82%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 73.89% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 17.63% की उपलब्धि दर्ज की गई है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- बैंकों द्वारा फूड और ऐग्रो उद्योगों को सुविधानुसार MSME एवं कृषि क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। एमएसएमई में फूड और ऐग्रो उद्योगों का कितना हिस्सा है इसका डाटा सभी बैंकों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को डाटा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- भारत सरकार द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार कृषि प्रसंस्करण उद्योग MSME के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं।

प्रतिनिधि, नाबार्ड की टिप्पणी- उन्होने आगामी एसएलबीसी बैठक में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का सैक्टर-वार डाटा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एजेंसी-वार वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति निम्नानुसार सूचित की-

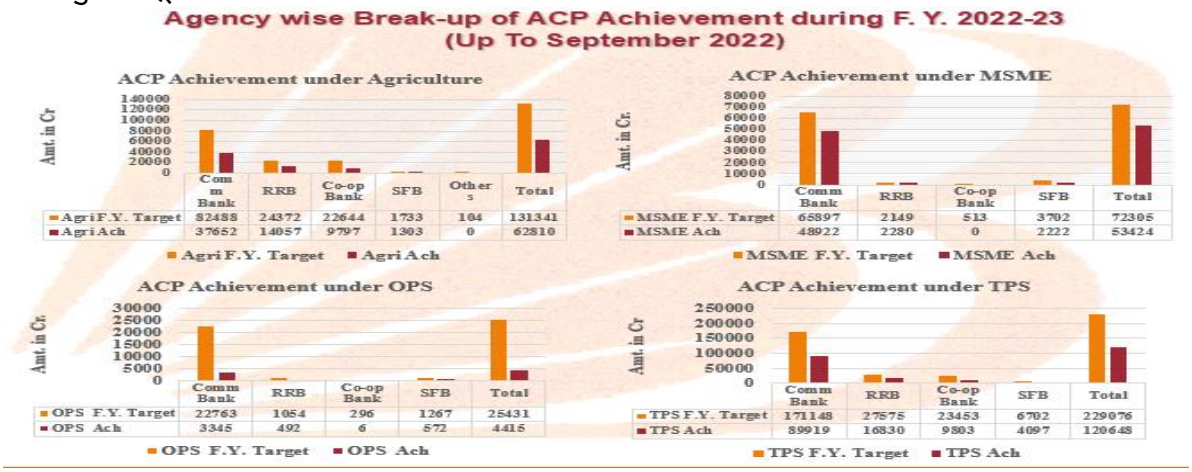

वार्षिक साख योजना के तहत 40% से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब और सिंध बैंक (14.45%), राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (21.72%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (21.73%) एवं आरबीएल बैंक (39.75%) से लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने के लिए अनुरोध किया।

(कार्यवाही: पंजाब और सिंध बैंक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एवं आरबीएल बैंक)

Potential Linked Plan (PLP) 2023-24

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनके PLP में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 2.75 लाख करोड़ ऋण प्रवाह का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि 20.05% है।
एसएलबीसी ने एलडीएम से ACP तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का पालन करने का अनुरोध किया है-

- संबंधित जिले की वार्षिक क्रेडिट योजना (एसीपी) और पीएलपी को समरूप करना।
- नियोजन से लेकर निष्पादन तक शाखाओं को शामिल करके एसीपी तैयार करना ताकि एसीपी अधिक यथार्थवादी और कार्यान्वयन योग्य हों।
- ACP लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 वर्ष के प्रदर्शन और जिले में उपलब्ध क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एसएलबीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशोंके अनुसार डीसीसी के सभी हितधारक, जिसमें डीएम या उनके प्रतिनिधि, नाबार्ड के डीडीएम, आरबीआई के एलडीओ, केंद्र/राज्य सरकार के संबंधित विकास विभाग और बैंकों के जिला समन्वयक शामिल हैं, के साथ उचित चर्चा के बाद ACP लक्ष्य तैयार किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)

Setting up of Brick and Mortar Branches

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में 95 स्थानों को ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित किया गया था और उसी के अनुसार एसएलबीसी, राजस्थान द्वारा सदस्य बैंकों को आवंटित किया गया है। उन्होने सूचित किया कि 95 केन्द्रों में से 26 केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। 63 केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु बैंकों द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं एचडीएफ़सी बैंक के कुल 4 केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु आज दिनांक तक बैंकों द्वारा कोंसेंट प्रदान नहीं की गई है। 35 शाखाएँ खोली जा चुकी हैं एवं 34 शाखाएँ कोलने हेतु लंबित हैं। बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक के 1-1 केन्द्रों पर पहले से शाखाएँ कार्यरत हैं किन्तु NIC द्वारा सूचित किया गया है कि इन शाखाओं को DBT-GIS पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया जा पा रहा है। बची हुई शाखाओं में से 23 शाखाएँ अगले 2 दिनों में खुल जाएंगी।

प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया कि उनको आवंटित दोनों केंन्द्रों पर शाखा खोलने के संबंध में प्रस्ताव अपने प्रधान कार्यालय को आगामी बोर्ड बैठक में मंजूरी हेतु भेजा है किन्तु उनके प्रधान कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिनिधि, एचडीएफ़सी बैंक ने सूचित किया वह तीनों केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु सहमत है एवं वह 15.02.2023 तक ही शाखा खोल पायेंगे।

किन्तु उक्त प्रस्ताव को सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया व इस संबंध में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र के द्वारा निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

प्रतिनिधि, बीआरकेजीबी ने सूचित कीया कि 2 केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु उन्हे उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो है और वह local authorities से स्थान प्रदान करने हेतु पत्राचार कर रहे हैं तथा 31.12.2022 तक शाखाएँ खोले जाने में असमर्थ हैं।

प्रतिनिधि, इंडियन ओवर्सीस बैंक ने सूचित किया कि उनको आवंटित तीनों केन्द्रों पर शाखा खोल दी गयी है।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- उत्तर क्षेत्रीय परिषद (NZC) में स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि 3000 से अधिक जनसंकया वाले वह ग्राम किनके 5 किमी की परिधि में शाखा कार्यरत नहीं है, वहाँ बैंकों को आवंटित केन्द्रों पर 31.12.2022 तक ब्रिक और मोर्टर शाखाएँ खोलना अनिवार्य है। साथ ही उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया की अपनी शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं एचडीएफ़सी के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से यथाशीघ्र consent प्रदान करने व एचडीएफ़सी बैंक से 31.12.2022 तक शाखा खोलना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: एचडीएफ़सी बैंक एवं सेंट्रल बैंक इफ इंडिया)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से उनकी समस्त शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित करने के संबंध में confirmation लेने का अनुरोध किया। साथ ही एसएलबीसी से अनुरोध किया कि इस संबंध में बैंकों से उनके नियंत्रकों के हस्ताक्षर से पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण लें।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 14.12.2022 तक की प्रगति इस प्रकार है:

Special Drive for Jan Suraksha Scheme						
	PMJJBY		PMSBY		APY	
	Target	Enrolled	Target	Enrolled	Target	Enrolled
29.06.2022	69,15,500	18,54,848 (27%)	96,73,911	46,87,057 (48%)	56,33,175	6,74,810 (12%)
14.12.2022	69,15,500	23,56,015 (34%)	96,73,911	55,16,114 (57%)	56,33,175	8,51,032(15%)
PROGRESS		5,01,167		8,29,057		1,76,222

उन्होने सूचित किया कि सितंबर 2022 तक प्रत्येक जन सुरक्षा योजनान्तर्गत 40% लक्ष्य अर्जित करने थे, पर जन सुरक्षा योजनों में विशेषकर PMJJBY एवं APY में प्रगति संतोषजनक नहीं है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि उचित कार्य योजना बनाते हुए सभी ग्राहकों को पात्रतानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कवर करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Atal Pension Yojna:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:

Progress upto 15.12.2022						
Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 15.12.2022	% Ach.
PSB		4142	80	331360	341191	103%
RRB		1575	80	126000	104567	83%
SFB		247	50	12350	6755	55%
Private	Other Private Banks	349	30	10470	3298	31%
	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	910	80	72800	5531	8%
Co-Op.		462	20	9240	3	0%
Total		7685		562220	461345	82%
* Data received from PFRDA						

राज्य में कुल 5,62,220 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 15.12.2022 तक 4,61,345 (82%) नामांकन किए गए हैं जो कि सरहनीय है। अटल पेंशन योजनान्तर्गत एजेंसी-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- वाणिज्यिक बैंक-103%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-83%
- स्माल फ़ाइनेंस बैंक-55%
- एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एवं एक्सिस बैंक-8%
- सहकारी बैंक-0%

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति कि टिप्पणी- एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एवं एक्सिस बैंक का प्रदर्शन असराहनीय है। उन्होने राज्य सरकार से सरकारी योजनान्तर्गत खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों से सरकारी व्यवसाय वापस लेने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि SNA खातों का आवंटन बैंकों के सरकारी योजनान्तर्गत प्रदर्शन के अनुरूप होना चाहिए।

संयुक्त शसान सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार कि टिप्पणी- निजी बैंकों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। अगली एसएलबीसी बैठक से खराब प्रदर्शन वाले बैंकों द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। उन्होने निजी बैंकों से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक)

साथ ही उन्होने सदन को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सरकारी व्यवसाय के आवंटन हेतु बैंकों के सरकारी योजनान्तर्गत प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। SNA खाता खोलते समय बैंक द्वारा सरकारी योजनान्तर्गत प्रदर्शन को वेटेज दिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी समझे और मात्र सरकारी व्यवसाय लेने हेतु सरकारी योजनान्तर्गत कार्य ना करें।

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि जिला करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर एवं सिरोही को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है जिनमे से करौली ज़िले में 100% डिजिटलिकरण हो गया है। 100% डिजिटल ज़िलों हेतु करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमर एवं सिरोही की प्रगति निम्नानुसार है:

Status of 100 % Digital District - Karauli - Ajmer - Dholpur - Sirohi - Jaisalmer

Sr. NO.	District	Months	Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for Businesses (Current Accounts)	
			Eligible Operative Savings Accounts		% Coverage with at least one of the digital modes of payment				Total No. of Eligible Operative Current/ Business Accounts	% Coverage with at least one of the digital modes of payment
			No. of Accounts	Of which, no. of women accounts	Total No. of Accounts covered	All Accounts	Out of total no. of women accounts (66), no of women accounts covered	women accounts		
1	Karauli	Nov-22	12.85 Lakhs	5.71 Lakhs	12.82 Lakhs	99.81	5.69 Lakhs	99.73	0.16 Lakhs	99.39
2	Ajmer	Sep-22	36.09 Lakhs	15.64 Lakhs	30.85 Lakhs	85.47	10.96 Lakhs	70.08	1.21 Lakhs	76.23
3	Dholpur	Sep-22	10.50 Lakhs	4.81 Lakhs	9.60 Lakhs	91.42	4.33 Lakhs	90.05	0.13 Lakhs	75.24
4	Sirohi	Sep-22	9.59 Lakhs	4.02 Lakhs	8.37 Lakhs	87.25	3.66 Lakhs	91.08	0.19 Lakhs	71.23
5	Jaisalmer	Sep-22	6.61 Lakhs	2.71 Lakhs	6.06 Lakhs	91.74	2.42 Lakhs	89.26	0.18 Lakhs	60.07

उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वे ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग उत्पादों के संबंध में सक्षम करें और एसएलबीसी पोर्टल पर प्रगति की मासिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

KCC Saturation Drive: District Level Special KCC Campaign for Animal Husbandry and Fisheries Farmers

पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड

सुविधा प्रदान करने के लिए 15 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान को फिर से शुरू करना सूचित किया है जिसके तहत प्रगति निम्नानुसार है:

Progress under KCC Campaign for Animal Husbandry & Fisheries from 15.11.2021 to 09.12.2022							
Sr. No.	Particulars		Cumulative No. of Applications under Animal Husbandry				
			Received	Accepted	Sanctioned	Rejected	Pending
A	All Banks	Animal Husbandry	1,41,884	1,34,841	75,473	58,309	1,059
B		Fisheries	448	445	92	337	16

सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि अभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का सकारात्मक निस्तारण सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में 1,95,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 89,008 आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से 72137 आवेदनों में रु. 6729.97 लाख वितरित किए गए हैं जो असंतोषजनक है। 16,871 स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है।

उन्होने सभी बैंकों से इनमे ऋण वितरण करने एवं जिन स्वीकृत आवेदनों में ऋणी से बैंक का संपर्क नहीं होने के कारण ऋण वितरण नहीं किया जा पा रहा है, उन खातों को पोर्टल से हटाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 14 12 2022					Low Performing Banks as on 14 12 2022				
Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Account)	Total Disb (Account)	% disbusement against Target	Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Account)	Total Disb (Account)	% disbusement against Target
1	Bank of India	4330	4922	113.67	1	HDFC Bank	7903	293	3.71
2	Bank of Baroda	17880	15854	88.67	2	ICICI Bank	12989	269	2.07
3	State Bank of India	33931	28790	84.85	3	AU Small Finance bank	7230	112	1.55
4	Bank of Maharashtra	1260	697	55.32	4	Kotak Mahindra Bank	2396	7	0.29
5	Central Bank of India	5423	2511	46.30	5	Axis Bank	6515	6	0.09
6	Indian Bank	4582	1676	36.58	6	Bandhan Bank Ltd.	8029	1	0.01
7	Union Bank of India	9248	3228	34.90	7	IndusInd Bank	4161	0	0.00
8	Indian Overseas Bank	2312	792	34.26	8	Yes Bank Ltd.	3573	0	0.00

उन्होने सूचित किया कि कुल आवेदन स्वीकृति में एजेंसी-वार बैंकों का हिस्सा इस प्रकार है - वाणिज्यिक बैंक- 92.62%, निजी बैंक- 3.60%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 3.37%, स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 0.41%।
सभी सदस्य बैंकों, विशेषकर कम प्रगति वाले बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करें और स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 02.12.2022 तक 9,04,560 खातों में कुल रुपये 8,665.12 करोड़ (55.64%) का ऋण वितरण किया गया।

दिनांक 02.12.2022 तक श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है:

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt.
1	Shishu	6,27,799 (69%)	1,908.99
2	Kishore	2,34,467 (26%)	3,720.15
3	Tarun	42,294 (5%)	3,035.98
	Total	9,04,560 (100%)	8,665.12

स्टैंड अप इंडिया योजना Stand Up India Scheme (SUI)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 15.11.2022 तक राज्य में 7,225 आवेदनों में राशि रु. 1647.95 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए एवं 4,249 खातों में रु 719.46 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.11.2022 तक रु. 238.83 करोड़ के 1008 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं 226 खातों में रु 28.98 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

उन्होने सदन को सूचित किया कि समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। उन्होने बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में ऋण वितरण करने एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण कवर करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

National Rural Livelihood Mission

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य 91,100 के सापेक्ष दिनांक 09.12.2022 तक 55,671 खातों (61.11%) में 784.60 करोड़ (54.49%) का ऋण वितरण किया गया है।

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक विशेषकर इंडियन ओवरसीज़ बैंक (2.90%), पंजाब और सिंध बैंक(0.00%), एक्सिस बैंक (0.00%) एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (0.00%) से लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया।

(कार्यवाही: इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, एक्सिस बैंक एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

NRLM योजना के तहत वाणिज्यिक बैंकों ने 39.95%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 38.14%, निजी बैंक ने 1.91% एवं सहकारी बैंक द्वारा 0.00% ऋण प्रदान किए हैं।

DAY- National Urban Livelihood Mission

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 6,000 व्यक्तियों, 136 समूहों एवं 2,763 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 24.11.2022 तक उपलब्धि क्रमशः 797 (13.28%), 3 (2.21%) एवं 329 (11.91%) रही है। लक्ष्यों के सापेक्ष उपयुक्त गुणवत्ता वाले पर्याप्त आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित नहीं किए है।

प्रतिनिधि, DAY-NULM, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि योजनान्तर्गत विभाग द्वारा बैंकों को 4000 आवेदन प्रेषित किया गए हैं, जिनमे से 1220 आवेदन स्वीकृत हुये हाइनेवम 1150 आवेदनों में ऋण वितरण किया जा चुका है।

Prime Minister Employment Generation Programme

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 09.12.2022 तक की प्रगति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया:

- राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 114.48 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 09.12.2022 तक 1104 परियोजनाओं हेतु राशि रू 54.60 करोड़ (47.69%) का ऋण वितरण किया गया है। इस उपलब्धि पर उन्होने बैंकों को बधाई दी।

Bankwise PMEGP progress as on 09.12.2022															(Amt. Rs. In Cr.)
Sr. No.	Margin Money Targets for F.Y. 22-23	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank			Margin Money Claimed			MM Disbursed			Returned		
		No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach
A	114.48	5453	260.52	1879	106.13	92.71	1195	60.49	52.84	1104	54.60	47.69	2294	81.57	31.31

PMEGP के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 09.12.2022					Lowest Performing Banks under as on 09.12.2022				
Sr. No.	Banks	Targets FY 2022-23 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed	Sr. No.	Banks	Targets FY 2022-23 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed
1	BANK OF BARODA	12.5	20.58	164.61	1	STATE BANK OF INDIA	19.10	4.74	24.80
2	CENTRAL BANK OF INDIA	5.05	4.57	90.59	2	INDIAN BANK	3.70	0.80	21.49
3	CANARA BANK	5.3	4.00	75.53	3	RMGB	6.54	1.29	19.74
4	PUNJAB NATIONAL BANK	13.74	7.83	56.95	4	UCO BANK	4.60	0.76	16.57
5	PUNJAB AND SIND BANK	1.49	0.83	55.68	5	ICICI BANK LIMITED	4.05	0.38	9.42
6	BRKGB	8.1	3.39	41.80	6	IDBI BANK	2.20	0.11	4.93
7	UNION BANK OF INDIA	6.2	2.56	41.21	7	HDFC BANK	3.50	0.00	0.00
8	INDIAN OVERSEAS BANK	2.56	0.88	34.38	8	AXIS BANK LTD	2.50	0.00	0.00
Source: PMEGP Portal									

उन्होने योजनांतर्गत न्यूनतम प्रदर्शन वाले बैंकों से इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आरएमजीबी, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक एवं एक्सिस बैंक)

योजनांतर्गत वाणिज्यिक बैंक का 90.25%, निजी बैंक द्वारा 2.13%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 7.61% एवं सहकारी बैंकों का 0.00% योगदान है।

PMFME Scheme

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 14.12.2022 तक एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Progress under PMFME during FY 2022-23 as on 14.12.2022				
S. No.	Particulars	Target (No. of A/c)	Achievement	Pending Applications
A	Public Sector Bank Total	1524	78	94
B	Private Sector Bank Total	418	16	22
C	RRB Total	321	13	15
D	Co-Operative Bank Total	43	0	0
E	Small Finance Bank Total	75	6	2
	Rajasthan Total	2382	113	133

प्रतिनिधि, PMFME, राजस्थान सरकार ने बैंकों से PMFME योजना के fliers अधिकतम शाखाओं में प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही बैंकों से अनुरोध किया कि PMFME के आवेदन लेते समय ही आवेदनों की जांच करने एवं स्वीकार किए गए आवेदनों की सूचना संबन्धित विभाग को देने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 06.12.2022 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under AIF during F.Y. 2022-23 as on 06.12.2022															Amt. Rs. in Cr.
Sr. No.	Particulars	Target for F. Y. 2022-23	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned App. Approved by Bank & pending for Disb.		Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank		Application Pending with Bank		Application Rejected by Bank		% Achievement
		Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
A	PUBLIC SECTOR BANKS TOTAL	2054	237	386.28	146	227.08	35	70.42	111	156.66	31	78.73	60	80.48	7.63
B	PRIVATE SECTOR BANKS TOTAL	730	107	166.35	44	65.04	21	31.55	23	33.49	60	97.13	3	4.18	4.59
C	REGIONAL RURAL BANKS TOTAL	545	16	15.67	11	10.20	2	2.80	9	7.40	5	5.48	0	0.00	1.36
D	COOPERATIVE SECTOR BANKS TOTAL	182	10	1.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1.33	0	0.00	0.00
E	SMALL FINANCE BANK TOTAL	95	16	30.48	7	12.02	0	0.00	7	12.02	9	18.46	0	0.00	12.70
	RAJASTHAN TOTAL	3606	386	600.11	208	314.33	58	104.77	150	209.57	115	201.12	63	84.66	5.81

उन्होने कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojna (IGSCCY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य में 5,00,000 के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 09.12.2022 तक कुल प्राप्त 3,13,846 आवेदनों के सापेक्ष कुल 42,765 (8.56%) आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है जो कि असंतोषजनक है।

IGSCCY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 09.12.2022					Low Performing Major Banks as on 09.12.2022				
S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Sanctioned against Target	S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Sanctioned against Target
1	BANK OF BARODA	47887	7976	16.66	1	HDFC BANK	20448	649	3.17
2	STATE BANK OF INDIA	99079	15641	15.79	2	ICICI BANK LIMITED	34881	1054	3.02
3	BANK OF MAHARASHTRA	4029	348	8.64	3	PUNJAB AND SIND BANK	4273	116	2.71
4	PUNJAB NATIONAL BANK	53550	4025	7.52	4	CENTRAL BANK OF INDIA	17466	466	2.67
5	INDIAN OVERSEAS BANK	7342	503	6.85	5	INDIAN BANK	13227	270	2.04
6	RMGB	14735	933	6.33	6	IDBI BANK	5587	33	0.59
7	UCO BANK	18275	1122	6.14	7	YES BANK	6658	0	0.00
8	BANK OF INDIA	14042	728	5.18	8	KOTAK MAHINDRA BANK	5357	0	0.00
9	UNION BANK OF INDIA	23345	1086	4.65	9	INDUSIND BANK	7708	0	0.00
10	AU SMALL FINANCE BANK	11397	506	4.44	10	AXIS BANK	13742	0	0.00

कुल स्वीकृति में वाणिज्यिक बैंकों का 77.31%, निजी बैंकों का 4.07%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 4.45%, स्माल फ़ाइनेंस बैंक का 1.18% एवं अन्य बैंकों का 12.93% योगदान है।

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे सभी लंबित आवेदनों को मेरिट के आधार पर जल्द से जल्द निपटाएं, सभी स्वीकृत आवेदनों को वितरित करें और पोर्टल पर भी अपडेट करें। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार उन सभी पीएमएमवाई लाभार्थियों को कवर करने का अनुरोध किया, जिन्हें 01 अक्टूबर 2021 को या उसके बाद 50,000 रुपये (शिशु श्रेणी) तक का ऋण दिया गया है एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग को जानकारी जमा करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने खराब प्रदर्शन वाले बैंकों से अनुरोध किया कि वह योजनान्तर्गत प्रगति करने में आ रही बाधाओं के संबंध में सदन को सूचित करें जिससे उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- पिछली एसएलबीसी बैठक के सापेक्ष सकारात्मक प्रगति हुई है। खराब प्रगति वाले बैंकों के साथ राज्य सरकार अलग से बैठक कर इनके प्रदर्शन की समीक्षा करें।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

Mukhya Mantri Laghu udyog Protsahan Yojna (MLUPY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 24.11.2022 तक योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana														
S. No.	Particulars	Progress as on 24.11.2022 (Amt. in Rs. Cr.)												
		Target	Forwarded (FI)		Sanction (FI)		Disbursement		Rejection (FI)		Pending (FI)		% Ach
		A/c	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	
A	Rajasthan	10780	14374	3201.17	5982	1678.44	5208	976.28	1624	119.45	6768	1403.29	48.31

MLUPY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 24.11.2022						Low Performing Major Banks as on 24.11.2022					
S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Sanctioned against Target	S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Sanctioned against Target
		Total App.	Total App.	Amt (In Cr)				Total App.	Total App.	Amt (In Cr)	
1	BANK OF BARODA	1076	885	200.45	82.25	1	PUNJAB AND SIND BANK	110	23	7.39	20.91
2	BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN	1026	765	52.40	74.56	2	INDIAN BANK	278	52	9.74	18.71
3	AU SMALL FINANCE BANK	353	262	39.32	74.22	3	HDFC BANK	424	79	68.85	18.63
4	CANARA BANK	444	326	51.70	73.42	4	BANK OF MAHARASHTRA	111	17	15.26	15.32
5	INDIAN OVERSEAS BANK	188	130	5.83	69.15	5	AXIS BANK	194	29	13.50	14.95
6	IDBI BANK	179	111	12.23	62.01	6	ICICI BANK LIMITED	579	59	49.92	10.19
7	BANK OF INDIA	389	238	26.55	61.18	7	YES BANK	80	8	3.41	10.00
8	RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK	708	418	19.68	59.04	8	INDUSIND BANK	75	3	2.53	4.00

उन्होने कम प्रगति करने वाले बैंकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक एवं इंडसइंड बैंक)

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करें और सभी स्वीकृत आवेदनों में वितरण करें। साथ ही पोर्टल पर प्रगति को नियमित आधार पर अपडेट करने और सब्सिडी का दावा करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna (IMSUPY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 216 लाभार्थियों को रु. 12.80 करोड़ (21.60%) का ऋण वितरण किया गया है एवं रु 241.80 करोड़ के 4587 आवेदन लंबित हैं। 8178 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। लंबित आवेदनों की संख्या एवं अस्वीकृति प्रतिशत बहुत अधिक है जो स्वीकारीय नहीं है।

कुल स्वीकृति में वाणिज्यिक बैंकों का 44.61%, निजी बैंकों का 0.87%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 54.52% एवं अन्य बैंकों का 0.00% योगदान है।

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटान करें और सभी स्वीकृत आवेदनों का भुगतान करें। साथ ही नियमित आधार पर पोर्टल पर प्रगति को अपडेट करने और सब्सिडी का दावा करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- भारतीय स्टेट बैंक ने 150 के लक्ष्य के सापेक्ष 73 आवेदन स्वीकृत किए हैं एवं 12 आवेदनों में ऋण वितरण किया है। उन्होने भारतीय स्टेट बैंक से योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अद्यतिति करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

- निजी बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक है।
- कई बैंकों द्वारा ऋण वितरण के बाद सब्सिडि क्लेम नहीं की जाती। उन्होने सभी बैंकों से सब्सिडि क्लेम करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- इतनी अधिक अस्वीकृति प्रतिशत के कारणों की बैंकों एवं विभाग द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि PMFBY के अंतर्गत प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि 31.12.2022 है। उन्होने सभी बैंकेर्स से निवेदन किया कि 31.12.2022 तक प्रीमियम डेबिट कर लें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2022 के अंतर्गत दिनाँक 25.12.2022 तक केंद्रीय पोर्टल (NCIP) पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Particulars	
1	Application Count	1,21,01,222 (Nos.)
2	Total Sum Insured	15,215.10 (Rs. In Cr)
3	Total Farmer's Share	284.52 (Rs. In Cr.)
4	Gross Premium	1,730.50 (Rs. In Cr)

उन्होने सूचित किया कि आईसीआईसीआई बैंक का PMFBY के अंतर्गत पोर्टल पर प्रीमियम शून्य दर्शा रहा है एवं आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि से सही डाटा पोर्टल पर अद्यतिति करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: आईसीआईसीआई बैंक)

Issues pending

कृषकों के आंकड़े गलत विलेज मेपिंग एवं अन्य तकनीकी कारणों से NCIP Portal पर अंतिम तिथि तक अद्यतन नहीं हो पाये है। उक्त के संबंध में एसएलबीसी के द्वारा कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार से challan reconciliation एवं Pending Data Entry हेतु खरीफ 2022 मौसम के लिए PMFBY पोर्टल पुनः Reopen करवाने हेतु अनुरोध करने का श्रम करवाये।

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्रांक F 6 (III) CAG /CI/ PMFBY/ HLC/ 20 ( ) / 2022-23 /367 -69 दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रकरण हाई पावर कमेटी के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया है। उक्त सभी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा पात्र किसानों को फसल बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा क्लेम का लाभ दिलवाने हेतु उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2022-23 में सितंबर, 2022 तिमाही तक राज्य में 7532 छात्रों को राशि रू 259.82 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 30.09.2022 तक 40,830 खातों में रु 2178.64 करोड़ की राशि outstanding है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 4655 खातों में रु 169.22 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

Sector wise NPA Position as on 30th September, 2022

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य में क्षेत्र वार NPA निम्नानुसार है-

कुल एनपीए - **4.23%**

कृषि- **8.42%** एमएसएमई- **3.46%**

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- **2.77%** कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- **5.69%**

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-

कुल कृषि- **69.04%** कुल एमएसएमई- **24.91%** कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- **6.05%**

Position of NPAs in respect of Schematic Lending, Certificate cases and Recovery of NPA

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राको रोड़ा एवं सारफेसी के तहां निम्नानुसार प्रकरण लंबित हैं-

RACO (RODA) Act

Cases Pending as on 31/03/2022	Cases filed during FY 2021-22	Cases where amount recovered	Cases where Physical Possession has been taken	Cases Pending		Out of which, cases pending more than 12 months	
No.	No.	No.	No.	No.	Amt.	No.	Amt.
145346	12697	13969	12	144074	3297 Cr	92806	2012 Cr

SARFAESI Act

Cases Pending as on 31/03/2022	Cases filed during FY 2022-23	Cases where Amount recovered	Cases where Physical Possession has been taken	Cases Pending		Out of which, cases pending more than 2 months	
No.	No.	No.	No.	No.	Amt.	No.	Amt.
1176	1399	546	26	2029	337 Cr.	1384	229 Cr.

उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि राको-रोड़ा में बैंकों की बकाया राशि की वसूली हेतु बैंकों का सहयोग करें। साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) की बैठक संबन्धित विभाग द्वारा समय प्रदान नहीं कर पाने के कारण नहीं हो पायी है। उन्होने राजस्व विभाग से अनुरोध किया कि उक्त उपसमिति का आयोजन करवाने हेतु उचित समय प्रदान करें।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।